

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 364]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 28 जून 2018—आषाढ़ 7, शक 1940

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 जून 2018

क्र. एफ. 7-9-2007-उन्तीस-1.—भारत सरकार के उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के पत्र क्रमांक 9-5/2014-बी.पी. II, दिनांक 1 सितम्बर 2017 के पालन में, पूर्व में “कल्याणकारी एवं हॉस्टल योजना” के संबंध में जारी अधिसूचना क्रमांक 35 क्र. एफ. 7-9-2007-उन्तीस-1, भोपाल, दिनांक 18 जनवरी 2018 के दिशा-निर्देश के बिन्दु क्रमांक 3.3 को विलोपित करते हुए, राज्य शासन नवीन बिन्दु क्रमांक 3.3 निम्नानुसार प्रतिस्थापित करता है:—

“3.3 चयनित संस्थाओं के प्रत्येक रहवासियों को प्रतिमाह अधिकतम 15 किलोग्राम खाद्यान्न (गेहूं एवं चावल) की पात्रता होगी:

परन्तु इस पात्रता में राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से निर्धारित खाद्यान्न की अधिकतम आवंटन सीमा एवं राज्य में पात्र संस्थाओं के हितग्राहियों की संख्या के आधार पर कमी/वृद्धि की जा सकेगी.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. के. चन्देल, उपसचिव.